श्री सभापति : क्वेश्चन - 124 है I have passed on to Question No. 124. Rules do not permit me.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं इस रूल के तहत, रूल कहता है यह **(व्यवधान)**

श्री सभापति : रूल मुझे स्टैंडाड हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : तो मैं इसीलिए आपसे.... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : क्वेश्चन-124

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।

श्री सभापति : मैं आपको समझा दूंगा, आप बाद में मिलियेगा तो।

किसानों को गेहूं के बढ़े हुए वसूली मूल्य का लाभ

*124. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :†

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 21 अप्रैल, 1990 को गेहूं के वसूली मूल्य में 15 रु० प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वे किसान जिन्होंने अपने उत्पादों को सरकारी एजेंसियों को इस तिथि से पूर्व बेचा था, इन बढ़े हुए मूल्यों का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो गेहूं के बढ़े हुए वसूली मूल्यों के अतिरिक्त लाभ को सरकार द्वारा उन सभी किसानों को, जिन्होंने इस वर्ष अपने उत्पाद सरकारी एजेंसियों को बेचे हैं, न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

†The question was actually asked on the floor of the House by Sardar Jagjit Singh Aurora.

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जिन किसानों ने अपना गेहूं भारतीय खाद्य निगम और राज्य की वसूली एजेंसियों को बढ़ा दिए गए 215 रु० प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य को वास्तव में लागू करने से पूर्व गेहूं के 200 रु० प्रति क्विंटल के पूर्व संशोधित समर्थन मूल्य पर बेच दिया था, उन्हें अन्तर मूल्य का भुगतान करने के बारे में 13 जुलाई, 1990 को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: I am glad that you have issued instructions and people are going to get the extra Rs. 15 per quintal. May I please be told as to what is the procedure to ensure that the payments would be made to the actual producers and not to the middlemen?

श्री राम पूजन पटेल : माननीय सभापति जी, सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि किसानों को पैसा मिलने के लिये जिससे कि उसमें कोई धांधली न हो सके, एकाएउंट पेई चैक हों किसानों के नाम काटे जायें जिससे कि उनको पैसा मिल सके और उसमें किसी प्रकार की बीच में धांधली न हो सके।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Sir, I have raised this question is that a large amount of wheat and the other produce is procured through middlemen. In the first instance, the small farmer sells it to a middleman when he needs money and then that is brought to the mandis, and then it is sold through these middlemen to the Food Corporation. Is the Minister aware of this? Have they found any way of overcoming this?

श्री राम पूजन पटेल : माननीय सभापति जी, यह बिचौलियों के माध्यम से सरकार नहीं लेती है बल्कि जो राज्य सरकारें हैं उनकी एजेंसियां हैं वह किसानों से गेहूं या और खाद्यान्न पदार्थों को खरीदती हैं और उसके बाद जब एफ० सी० आई० गोदामों में ले लिया

जाता है, एफ० सी० आई० उनको भुगतान कर देता है। इसमें और कोई अनियमितता हो तो माननीय सदस्य हम लोगों को बतायेंगे तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री शांति त्यागी : माननीय सभापति जी, बहुत सी जगहें यू० पी० में, हरियाणा में और पंजाब में बेमौसम की बारिश की वजह से जब वह फसल उठ रही थी, भाग गया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बात सही है कि सरकारी एजेंसियों ने भीगे-हुए गेहूं को खरीदने से इंकार कर दिया था।

श्री राम पूजन पटेल : माननीय सभापति जी, इसकी ऐसी कोई सूचना मेरे पास अभी तक नहीं आयी है कि सरकारी एजेंसी ने लेने से इंकार किया हो। और कोई जानकारी त्यागी जी को हो तो हम लोगों को बतायें, उसको हम देखेंगे।

श्री शांति त्यागी : इनको अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है!

श्री सभापति : आप बता दीजिए।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: There is a wide gap between the procurement of wheat and paddy and the issue price of wheat and rice. It is reported in the press that the Bhanu Pratap Singh Committee has recommended for the abolition of the Food Corporation of India and to replace it by 'Food Stamp'. I would like to know, what is the reaction of the Government in this regard to abolish lock stock and barrel this* Food Corporation of India ...

MR. CHAIRMAN: You use parliamentary language.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: I am withdrawing that word *and replacing it with the words 'white elephant'. Does the Government propose to abolish this white elephant Food Corporation of India and replace it by Food Stamp so that both the producer as well as the consumer could get some help? I would like to seek this information from the Minister.

श्री राम पूजन पटेल : माननीय सभापति जी, भारतीय खाद्य निगम को जहां माननीय सदस्य ने कहा कि समाप्त कर दिया जाए मैं समझता हूं किसानों का गेहूं बिचौलिया जो खरीदेगा, व्यापारी जो खरीदेगा वह कम दाम में खरीदेगा और जो हम खरीदते हैं वह ज्यादा रेट पर खरीदते हैं। उनके द्वारा खरीदने पर उपभोक्ता और उत्पादकता दोनों को बड़ा नुकसान होगा। सरकार हमेशा यह सोचती है कि खाद्यान्न को वसूल करके सुरक्षित रखे और इसके लिए वह कृषकों को लाभकारी मूल्य भी देता है। सरकार यह भी चाहती है कि अनाज का स्टॉक बनाए रखा जाए जिससे उपभोक्ताओं को हमेशा मिलता रहे और इसलिए भारतीय खाद्य निगम को समाप्त करना है मैं समझता हूं न देश के हित में होगा और न ही जनहित में होगा।

Development of Usar Land

*125. SHRI SHAMIM HASHMI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is a large area of Usar land in Uttar Pradesh and other States and if so, the details thereof; State-wise, indicating the area as in 1950 and in 1990;

(b) whether a Seminar on Usar Revolution was organised recently at Faizabad, UP and if so, the details thereof and the follow up action taken in this regard; and

(c) whether there have been similar seminars/discussions in the past on this subject organised by the ICAR/Agricultural Universities, Central Soil Salinity Research Institute, Karnal etc. and if so, the details thereof and follow up action taken thereon and the achievements made so far?

*Not recorded.